लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2741
04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपास उत्पादकता मिशन

2741. श्री जी. कुमार नायकः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कपास उत्पादकता मिशन के अंतर्गत अनुमोदित आवंटन का ब्यौरा क्या है और विशेषकर रायचूर और कर्नाटक सहित राज्य-वार और जिला-वार निर्धारित तथा आवंटित धनराशि कितनी है;

(ख) 140 मिशन जिलों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा और इसमें रायचूर को शामिल करने के क्या कारण हैं;

(ग) उत्पादकता संवर्धन, उच्च सघनता वाली रोपण प्रणाली (एचडीपीसी), एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास, बीज प्रतिस्थापन, किसानों को शामिल करने और प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए कर्नाटक में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक में स्थापित अथवा आधुनिक बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कपास परीक्षण प्रयोगशालाओं, कस्तूरी कॉटन भारत ट्रेसिबिलिटी सुविधाओं तथा ओटाई और प्रसंस्करण इकाइयों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) कर्नाटक में विशेषकर रायचूर के लिए निर्धारित कार्यान्वयन की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और निगरानी तंत्र का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): कपास उत्पादकता मिशन (कपास क्रांति) को सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31) के लिए 5,659.22 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय से दिनांक 5 मई, 2026 को अनुमोदित किया गया था। इसमें से, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) द्वारा कार्यान्वित घटक-I (क) का परिव्यय 555.05 करोड़ रुपये है और कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा कार्यान्वित घटक-I (ख) का परिव्यय 3,804.17 करोड़ रुपये है। वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय कपास निगम और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित घटक-II और III के लिए क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

घटक-I (क) के तहत, कर्नाटक में रायचूर, चामराजनगर और धारवाड़ में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) के तहत कपास उत्पादकता से संबंधित गतिविधियों के लिए लगभग 11.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। घटक-I (ख) के तहत कर्नाटक को वर्ष 2026-27 के दौरान, 4,850.13 लाख रुपये (केन्द्र का हिस्सा: 2,910.08 लाख रुपये और राज्य का हिस्सा: 1,940.05 लाख रुपये) की राशि आवंटित की गई है। कर्नाटक सरकार ने घटक-I (ख) के तहत रायचूर जिले के लिए 1,100.81 लाख रुपये निर्धारित किए हैं।

(ख): घटक-1 (ख) के तहत, मिशन में शुरू में 14 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 140 संभावित जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों का चयन उनकी कपास उत्पादन क्षमता के आधार पर किया गया है। जिलों की सूची सांकेतिक है, और राज्यों के पास अपनी वार्षिक योजनाओं, आवश्यकताओं और/या निष्पादन के आधार पर कवर किए गए जिलों को संशोधित करने की सुविधा है। रायचूर को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह कर्नाटक के प्रमुख कपास-उत्पादक जिलों में से एक है।

(ग): कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2026-27 हेतु मिशन के घटक-I (ख) के तहत लक्षित लाभार्थियों सहित प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए जिला-वार भौतिक लक्ष्यों की सूचना दी है। विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया हैं।

इस मिशन में कर्नाटक के लिए वर्ष 2030-31 तक कपास का उत्पादन 40 लाख गांठ तक बढ़ाने और उत्पादकता को 860 किलोग्राम लिंट/हेक्टेयर तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिए गए वर्षवार लक्ष्य **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ): इसका विवरण इस प्रकार है:

(i) कपास परीक्षण प्रयोगशालाएं: मिशन के घटक-।। के तहत, देश भर में कपास उत्पादक जिलों के कलस्टरों में 50 कपास परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मिशन इन प्रयोगशालाओं के राज्य-वार या जिला-वार आवंटन को निर्दिष्ट नहीं करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में कार्यान्वयन के लिए, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) के साथ-साथ, योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उनका आवंटन निर्धारित किया जाएगा।

(ii) कस्तूरी कॉटन भारत ट्रेसेबिलिटी सुविधा: यह मिशन पात्र जिनिंग और प्रसंस्करण (G&P) फैक्ट्रियों द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत-प्रमाणित कपास गांठों के उत्पादन के लिए आउटपुट आधारित प्रोत्साहन प्रदान करता है। कर्नाटक में स्थित कारखानों सहित पात्र G&P फैक्ट्रियां, इसके प्रावधानों के अध्यधीन, योजना के तहत विचार हेतु पात्र हैं।

(iii) जिनिंग और प्रसंस्करण (G&P) इकाइयां: यह मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार, कस्तूरी कॉटन भारत-प्रमाणित कपास गांठों के उत्पादन के लिए पात्र G&P फैक्ट्रियों को आउटपुट-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ङ): कर्नाटक सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष-वार लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो **अनुबंध-II** में प्रस्तुत हैं।

मिशन के घटक-I (ख) के कार्यान्वयन की निगरानी मिशन के प्रावधानों के अनुसार गठित राज्य स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से की जाती है। निगरानी तंत्र रायचूर सहित मिशन के अंतर्गत कवर किए गए सभी जिलों पर लागू होता है। यह मिशन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष-वार लक्ष्यों की निगरानी हेतु प्रावधान उपलब्ध कराता है।

अनुबंध-I

उत्पादकता वृद्धि, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), क्लोजर स्पैसिंग (CS), एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS), इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग मैनेजमेंट (ICM) के लिए कर्नाटक में जिला-वार निर्धारित लक्ष्य

(क्षेत्रफल- हेक्टेयर में, लाभार्थी - संख्याओं में)

क्र.सं.	जिला	कर्नाटक में प्रौद्योगिकियों के उन्नयन (प्रदर्शन) के लिए लक्ष्य (2026-27)							
		हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS)		क्लोजर स्पेसिंग (CS)		एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS)		इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग मैनेजमेंट (ICM)	
		क्षेत्र	लाभार्थी	क्षेत्र	लाभार्थी	क्षेत्र	लाभार्थी	क्षेत्र	लाभार्थी
1	बल्लारी	450	225	1000	500	50	25	200	100
2	बेलगावी	50	25	0	0	0	0	200	100
3	चामराजनगर	0	0	200	100	1000	500	100	50
4	चित्रदुर्ग	0	0	400	200	1000	500	100	50
5	धारवाड़	500	250	0	0	3000	1500	300	150
6	गड़ग	0	0	300	150	0	0	100	50
7	हावेरी	0	0	300	150	0	0	100	50
8	कलबुर्गी	500	250	3000	1500	0	0	500	250
9	कोप्पल	0	0	0	0	0	0	200	100
10	मैसूर	0	0	700	350	900	450	200	100
11	रायचूर	2500	1250	3710	1855	0	0	600	300
12	विजयपुरा	100	50	2600	1300	50	25	400	200
13	यादगिरि	2500	1250	4000	2000	0	0	1000	500
	कुल	**6600**	**3300**	**16210**	**8105**	**6000**	**3000**	**4000**	**2000**

अनुबंध-II

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा वर्षवार प्रदान लक्ष्य

(उत्पादन - लाख गांठों में,
उत्पादकता- किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर में)

क्र. सं.	वर्ष	कर्नाटक		रायचूर	
		उत्पादन	उत्पादकता	उत्पादन	उत्पादकता
1	2026-27	26.00	559	6.59	646
2	2027-28	31.00	667	7.85	771
3	2028-29	34.10	733	8.64	847
4	2029-30	36.80	791	9.32	914
5	2030-31	40.00	860	10.14	994

***